



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

तई दिल्ली, मंगलवार फरवरी 23 1993/फाल्गुन 4, 1914

No. 107] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 1993/PHALGUNA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे इक वह भ्रमण संकलन के काम में
रक्ता जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कल्पण मासालय

सकलप

तई दिल्ली, 22 फरवरी 1993

वा आ 120(अ) —उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी द्वारा अन्य आदि वनाम भारत सरकार तथा अन्य आदि भूमि में 1940 का रिट प्राइविता (मिशिल) गव्या 930 में 16 नवम्बर, 1992 का दिन गण अपन बहुमत के लिये में, अब आगे के गाँधी साथ वह भी निर्देशिया है कि "भारत सरकार आगे में चार महीने + अन्त-पन्द्र" प्रन्द पिं वर्गों में से सामाजिक रूप से उत्तम जोगों/अगों (सम्पन्न वर्ग) को अन्य कानून के लिए नगर और अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड द्वारा प्रदान करा दूर आधारों पर वितरित कर्मी तथा दिनों 13 अगस्त 1900 के विवादित न्यायालय ज्ञापन का वर्णन्ययन ऐसे सामाजिक रूप से उत्तम अविनयों (सम्पन्न वर्ग) को भ्रमण करने के अध्ययन होगा।

2. इस तथ्य को मद्दतनकार रखने हुए वि अधारों त्रों कि "भ्रमण वर्ग" की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक मानदण्डों को निर्धारित करने में काफी विशेषीकृत नियेशा दी जानर पड़ेगी अत उक्त सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड के मत्रध में भारत सरकार से विस्तारित करने के लिए

एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्न-लिखित सदस्य होंगे —

1 न्यायमूर्ति राम नन्दन प्रद, र (संगीतनृत्य), पटना उच्च न्यायालय	अध्यक्ष
2 श्री पंड. पा. पना (गामाज दिजानी), भूगूँव अध्यक्ष (सब लोक भ्रमण आयोग)	महारप
3 श्री पा. पृष्ठ उच्छन, भूतत्व संशोध (कल्पण), भारत सरकार	सदस्य
4 श्री आर. जे. मनारिया, भूतत्व अध्यक्ष, राजपत्र वार्ड, राजपत्र नल यूनियन	सदस्य

यह निमिति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के क्रियान्वयन संबंधी उन अन्य सामलों में भी, उनमें आरे में भारत सरकार आवश्यक समझती, विभागीय करनी।

3 समिति का भूष्यालय दिनों भी अवश्यित होगा।

(1)

4. समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी कार्यविधियां स्वयं तैयार करेगी। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग वे सभी सूचनाएं और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और ऐसी महायता प्रदान करेंगे जो समिति द्वारा अपेक्षित होगी। यह आशा की जानी है कि राज्य सरकार और सघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा अन्य संबंधित इस समिति को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

5. यह समिति अन्य पिछड़े वर्गों में से "सम्पन्न वर्ग" को अलग करने सबधी सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड पर अपनी रिपोर्ट अधिक से अधिक 10 मार्च, 1993 तक प्रस्तुत कर देगी।

[स. 12011/16/93-वो. सी सी. (सी)]

एम. एस. पडित, संयुक्त सचिव
(प्रलम्पस्थक एवं पिछड़ा वर्ग)

MINISTRY OF WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd February, 1993

S.O. 120(E).—The Supreme Court, in its Majority Judgment in Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990, Indra Sawhney and Others etc. Vs. Union of India and Others etc., delivered on 16th November, 1992 has, inter alia, directed that "within four months from today the Government of India shall specify the bases, applying the relevant and requisite socio-economic criteria to exclude socially advanced persons/sections ('creamy layer') from 'Other Backward Classes' and further that the implementation of the impugned O.M. dated, 13th August, 1990 shall be subject to exclusion of such socially advanced persons ('creamy layer')."

2. Having regard to the fact that a lot of specialised inputs would be needed to determine the bases viz. socio economic criteria for identification of the 'creamy layer', it has been decided to set up an Expert Committee consisting of :

1. Justice Ram Nandan Prasad (Retd.)
High Court Patna .. Chairman
2. Shri M. L. Sahare (Social Scientist)
Former Chairman, U.P.S.C. .. Member
3. Shri P. S. Krishnan,
Former Secretary (Welfare) .. Member
Govt of India
4. Shri R. J. Majithia, former Chairman
Revenue Board,
Government of Rajasthan .. Member
Secretary

to make recommendations to the Government of India, in regard to the said socio-economic criteria. The Committee will also give recommendations on such other matters relating to the implementation of the judgment of the Supreme Court as the Government of India may consider necessary.

3. The Headquarters of the Committee will be located at Delhi.

4. The Committee will devise its own procedures in the discharge of its functions. All the Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and provide such assistance as may be required by the Committee. It is hoped that the State Governments and Union Territory Administrations and others concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the Committee.

5. The Committee shall submit its Report on the socio economic criteria for exclusion of the 'creamy layer' from Other Backward Classes latest by 10th March, 1993.

[No. 12011/16/93-BCC(C)]

M. S. PANDIT, Lt. Secy.
(M. & BC)